

खास-खबरें

जनसुनवाई में नागरिकों की समस्याएं सुनीं अधिकारियों को निराकरण के निर्देश



नईदुनिया, प्रतिनिधि, रायसेन: कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मंगलवार को नियमित जनसुनवाई आयोजित की गई। इसमें जिला पंचायत सीईओ कमल सोलंकी और अपर कलेक्टर मनोज उपाध्याय ने आमजन को समस्याएं सुनीं। अधिकारियों ने आवेदकों से उनकी समस्याओं के संबंध में सीधे संवाद कर संबंधित प्रकरणों की जानकारी ली। जनसुनवाई के दौरान प्राप्त आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई करते हुए समय-सीमा में निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई में विभिन्न विभागों से संबंधित समस्याओं को लेकर नागरिक पहुंचे। अधिकारियों ने आवेदकों की बात सुनकर संबंधित विभागों को प्रकरणों का परीक्षण कर नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए। इस दौरान डिप्टी कलेक्टर सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित रहे।

यूजीसी के इक्विटी विनियमों के विरोध में सर्व-समाज ने निकाला जुलूस

नईदुनिया, प्रतिनिधि, गंजबासौदा: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के 2026 के इक्विटी विनियमों को लेकर मंगलवार को गंजबासौदा में विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने प्रदर्शन किया। शीतला शक्ति धाम से शुरू हुआ जुलूस तहसील परिसर पहुंचा, जहां राष्ट्रपति के नाम एसडीएम अनुभा जैन को ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन में विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि, युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुईं। ज्ञापन का वाचन अमानसिंह राजपूत ने किया। प्रदर्शनकारियों ने विनियमों पर पुनर्विचार, व्यापक राष्ट्रीय विमर्श और सभी पक्षों से सुझाव व आपत्तियां आमंत्रित करने की मांग रखी। प्रदर्शन में ब्राह्मण दल, ब्राह्मण समाज, दांगी समाज, जैन समाज, सिंधी महापंचायत, अरोरा समाज, रघुवंशी समाज, अग्रवाल समाज, मोहेश्वरी समाज, गुसा समाज, राजपूत समाज और विदिशा महाराणा प्रताप राजपूत विकास समिति सहित विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

पीजी कॉलेज में अंबेडकर की तस्वीर हटाने का आरोप, एनएसयूआई ने किया प्रदर्शन



नईदुनिया, प्रतिनिधि, सीहोर: शासकीय पीजी कॉलेज में महापुरुषों की तस्वीरों को लेकर विवाद गहरा गया है। छात्र संगठन एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कॉलेज परिसर और प्राचार्य कक्ष में पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्राचार्य ने अपने कक्ष से डॉ. भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटा दी। इससे नाराज कार्यकर्ताओं और छात्रों ने महात्मा गांधी और डॉ. अंबेडकर की तस्वीरें हाथ में लेकर कॉलेज परिसर में प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने सीहोर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इसमें मामले को निष्पक्ष जांच कराने और प्राचार्य को तुरंत लिंबित करने की मांग की गई है। छात्रों ने कहा कि अगर प्राचार्य कक्ष में महापुरुषों की तस्वीरें सम्मानपूर्वक नहीं लगाई गईं और जल्द कार्रवाई नहीं हुई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे।

मेट्रिमोनियल प्लेटफॉर्म पर साढ़े सात लाख की ठगी, छह आरोपी गिरफ्तार

नईदुनिया प्रतिनिधि, मंदसौर: जिले में मेट्रीमोनियल प्लेटफॉर्म पर प्रोफाइल अपलोड करने वाली शामगढ़ निवासी एक महिला को झांसे में लेकर साढ़े सात लाख रुपये की ठगी करने वाले अंतरराज्यीय बिहार गिरोह के छह सदस्यों को मंदसौर पुलिस ने अलग-अलग राज्यों से गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 22 एंड्रॉयड मोबाइल फोन, 30 मोबाइल सिम और पांच एटीएम कार्ड बरामद किए हैं। इसके अलावा विभिन्न बैंक खातों में जमा आठ लाख रुपये से अधिक की राशि को फ्रीज कराया गया है।

पुलिस के अनुसार, शामगढ़ निवासी पीड़िता ने मेट्रीमोनियल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफाइल अपलोड की थी। इसी दौरान वह साइबर ठगों के संपर्क में आई और उनके झांसे में आकर साढ़े सात लाख रुपये गंवा बैठी। ठगी का पता चलने के बाद पीड़िता ने मंदसौर पुलिस



अधीक्षक विनोद कुमार मीना के समक्ष शिकायत दर्ज कराई।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक ने गिरोह की पहचान करने और आरोपियों तक पहुंचने के लिए विशेष टीम

गठित की। उप निरीक्षक कपिल सोराष्ट्री और उप निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह कनेश के नेतृत्व में पुलिस टीम ने लगातार प्रयास करते हुए आरोपियों के संबंध में सुराग जुटाए।

जयपुर में दबिश, बिहार से भी आरोपी पकड़ा: पुलिस टीम ने प्राप्त सुरागों के आधार

राष्ट्रीय पोषण माह के तहत जमगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र में जागरूकता कार्यक्रम

नईदुनिया प्रतिनिधि, बरेली: महिला एवं बाल विकास विभाग के तत्वावधान में 9वें राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत जमगढ़ आंगनबाड़ी केंद्र में पोषण जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम महिला एवं बाल विकास अधिकारी जुलेखा खान और सेक्टर सुपरवाइजर प्रियंका रघुवंशी के निर्देशन में हुआ। इसमें छह माह से छह वर्ष तक की आयु के बच्चों और महिलाओं ने भाग लिया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य, संतुलित आहार, स्वच्छता और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में जानकारी दी। बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए पोषणयुक्त आहार की आवश्यकता के बारे में भी बताया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुनीता शर्मा ने कहा कि पौष्टिक आहार के लिए महंगे खाद्य पदार्थ आवश्यक



नहीं हैं। घर में उपलब्ध अनाज, दाल, हरी सब्जियां और मौसमी फलों सहित अन्य खाद्य सामग्री से बच्चों और महिलाओं के लिए पौष्टिक व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं। उन्होंने महिलाओं को घरेलू सामग्री से विभिन्न पौष्टिक व्यंजन बनाने की विधि और उनके पोषण संबंधी महत्व की जानकारी दी। माताओं को छह माह की आयु के बाद बच्चों को उम्र के अनुसार पूरक आहार देने, भोजन में

पीडब्ल्यूडी की सड़क पर नपा कब तक पेचवर्क कराए जिम्मेदार ठेकेदार पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं

नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों से सवाल पूछे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर: मंडी क्षेत्र की जर्जर सड़क को लेकर आम जनता में पनप रहे भारी आक्रोश और सोशल मीडिया पर 30 सितंबर को प्रस्तावित चक्काजाम के वायरल मैसेज के बाद नगर पालिका अध्यक्ष प्रिंस राठौर खुद मैदान में उतर आए हैं। मंडी क्षेत्र के नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता पर रखते हुए नपाध्यक्ष सीधे लोक निर्माण विभाग के दफ्तर पहुंचे और अधिकारियों से सीधी बात की। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि मंडी की जनता परेशान हो रही है और पीडब्ल्यूडी की लापरवाही का खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। नपाध्यक्ष प्रिंस राठौर ने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को ज्ञापन सौंपकर अधिकारियों से सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि माता मंदिर से लेकर मंडी चौराहे और नरसिंहगढ़ नाका तक की सड़क पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। यह सड़क पीडब्ल्यूडी के क्षेत्राधिकार में आती है, फिर भी जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका



पहले ही साल दम तोड़ गई हर्डेटक तकनीक

गौरतलब है कि करीब दो से ढाई वर्ष पूर्व लगभग 30 करोड़ रुपये की लागत से 24 किलोमीटर लंबी सीहोर-श्यामपुर सड़क का निर्माण एमपीआरडीसी और पीडब्ल्यूडी के समन्वय से कराया गया था। इसमें प्रदेश की पहली फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक का इस्तेमाल करते हुए दावा किया गया था कि यह सड़क 10 साल तक नहीं उखड़ेगी, लेकिन पहली ही बारिश में सड़क की गुणवत्ता की पोल खुल गई। पैचवर्क के रूप में की गई मरम्मत भी पूरी तरह उधड़ चुकी है और गिट्टियां बिखर रही हैं।

इस पर लगातार पेंचवर्क का काम करा रही है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब सड़क निर्माण के महज एक साल के भीतर ही पूरी तरह उखड़ गई तो विभाग अब तक संबंधित ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट

करने या उस पर कार्रवाई करने से क्यों कतरा रहा है।

30 सितंबर को चक्काजाम का मैसेज वायरल: बता दें मंडी क्षेत्र की मुख्य सड़क के जानलेवा गड्ढों से परेशान होकर स्थानीय

कालिदास समारोह में विद्यार्थियों ने चित्रकला व श्लोक गायन में जीते पुरस्कार गंजबासौदा।

शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में विकासखंड स्तरीय कालिदास समारोह का आयोजन उत्साहपूर्ण एवं गरिमामय वातावरण में किया गया। समारोह में विकासखंड के विभिन्न विद्यालयों से विद्यार्थियों ने हिस्सा लेकर चित्रकला, श्लोक गायन सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिताओं के माध्यम से विद्यार्थियों ने कला, साहित्य और संस्कृत भाषा के प्रति अपनी समझ एवं रचनात्मकता का परिचय दिया। चित्रकला प्रतियोगिता के वरिष्ठ वर्ग में नवांकुर विद्यालय गंजबासौदा की उपासना जाट ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जबकि कनिष्ठ वर्ग में डॉल्फिन स्कूल के हर्षित अंबेडकर प्रथम रहे। श्लोक गायन के वरिष्ठ वर्ग में सांदीपनि विद्यालय की कु. प्रकाशा राजपूत ने पहला स्थान हासिल किया। कनिष्ठ वर्ग में संत जगन्नाथ संस्कृत विद्यालय के नितिन पाठक प्रथम रहे। प्रतियोगिताओं में निर्णायक की भूमिका भूपेंद्र सेन, वंदना भार्गव, स्वप्नदा डे और चंद्रम जायसवाल ने निभाई। उन्होंने निर्धारित मापदंडों के आधार पर विद्यार्थियों की प्रस्तुतियों का मूल्यांकन किया। कार्यक्रम में प्राचार्य एमसी शर्मा, प्रदीप चौरसिया, समीक्षा जैन, शिल्पाजना शर्मा, भारती पंथी, शिवा सिंह राजपूत, प्रशांत श्रीवास्तव सहित शिक्षक और विद्यार्थी उपस्थित रहे।

कार्यालय, राज्य वित्त आयोग मंत्रालय, वल्लभ भवन भोपाल (म.प्र.) क्रमांक 311 :-रा.वि.आ/ 2026 भोपाल, दिनांक 28/09/2026 अध्यक्ष, राज्य वित्त आयोग के विशेष सहायक/सलाहकार हेतु विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग में सैवधानिक व्यवस्था के अनुसार गठित राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष, के निजी स्थापना में 01 विशेष सहायक/सलाहकार के प्रतिनियुक्ति/सविदा के पद स्वीकृत है। इस पद पर योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करने की आवश्यकता है।

इच्छुक उम्मीदवार, पात्रता निर्धारण की शर्तें एवं भरे जाने वाले आवेदन प्रपत्र को राज्य वित्त आयोग के आधिकारिक वेबसाईट Http://sfc.mp.gov.in/ से डाउनलोड कर सकते हैं। सम्पूर्ण रूप से भरे हुये आवेदन पत्र को दिनांक 13.10.2026 को अपराह्न 3:00 बजे तक या उसके पहले तक मंत्रालय (VB-1) स्थित राज्य वित्त आयोग के कार्यालय के कक्ष क्र. 302-C, मंत्रालय भोपाल में रजिस्टर्ड डाक/व्यक्तिगत रूप से जमा किये जा सकते हैं।

राज्य वित्त आयोग उपरोक्तानुसार प्राप्त होने वाले आवेदनों को बिना कारण स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखते है।

सदस्य सचिव, राज्य वित्त आयोग, मंत्रालय, भोपाल, जी-19194/26

जनसुनवाई-कलेक्टर की पहल से ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान की प्रक्रिया तेज



नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा: कलेक्टर अंशुल गुप्ता ने जिला मुख्यालय पर संपन्न जनसुनवाई में प्राप्त विभिन्न शिकायतों एवं आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करते हुए अनेक मामलों का मौके पर ही निराकरण कराया।

लटेरी तहसील के ग्राम कोलापुरा निवासी बाबूलाल प्रजापति ने अपनी पट्टे की भूमि पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने तथा सोयाबीन फसल काटने की धमकी दिए जाने की शिकायत की। आवेदक ने बताया कि वह न्यायालय से प्रकरण जीत चुके हैं और भूमि पर कब्जा बना हुआ है। कलेक्टर ने लटेरी एसडीएम से वर्चुअल माध्यम से चर्चा कर निर्देश दिए। इसी प्रकार

सिरोंज तहसील के ग्राम वीरपुर निवासी फुल्ला धानक ने अपनी

चुनाव आयोग की स्पष्टता के बाद कांग्रेस के आरोपों की वास्तविकता सामने आई : रचना मेवाड़ा



कार्यप्रणाली से संबंधित आंतरिक मामला था। रचना सुरेंद्र मेवाड़ा ने कहा कि प्रपत्र-6 को लेकर भी जनता के बीच भ्रम उत्पन्न करने का प्रयास किया गया। चुनाव आयोग के अनुसार विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत प्रपत्र-6 के साथ संलग्न बादर घोषणा-पत्र को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वैध ठहराया गया है। वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण की अवधि के बाहर पूर्व निर्धारित नियम एवं प्रपत्र ही लागू हैं।

उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग द्वारा प्रत्येक पात्र मतदाता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं। विशेष शिविरों के आयोजन के साथ-साथ छूटे हुए लोगों के घर जाकर बूथ स्तर के अधिकारियों द्वारा प्रपत्र एकत्र करने की व्यवस्था भी की जा रही है। रचना सुरेंद्र मेवाड़ा ने

कहा कि लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक संस्थाओं के संबंध में आरोप लगाने के बजाय सभी राजनीतिक दलों को तथ्यों और आधिकारिक स्पष्टीकरण का सम्मान करना चाहिए। चुनाव आयोग के स्पष्ट वक्तव्य के बाद विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम की वास्तविकता जनता के सामने स्पष्ट हो गई है।

न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति (पी.ए.सी.एल. लि. के मामले में) सार्वजनिक सूचना

मध्य प्रदेश टीकमगढ़, भोपाल, निवाडी, कर्नाटक बेगलुरु ग्रामीण में स्थित पी.ए.सी.एल. लि. की संपत्तियों की ई-नीलामी

- भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सुबुत भट्टाचार्य बनाम भारतीय् प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले (सिविल अपील सं. 13301/2015) में तथा दूसरे संबंधित मामलों में, 2 फरवरी 2016 को पारित किए गए आदेश के तहत, पी.ए.सी.एल. लि. द्वारा खरीदी गई संपत्तियों की बिक्री करने के लिए, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर. एम. लोढा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था,ताकि बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीडर) से निवेशकों को भुगतान किया जा सके। उपरोक्त मामले में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेश दिनांक 8 अगस्त, 2024 के अनुसार, इस समिति ने मध्य प्रदेश टीकमगढ़, भोपाल, निवाडी, कर्नाटक -बेंगलुरु-ग्रामीण में स्थित पी.ए.सी.एल. लि की संपत्तियों की ई-नीलामी शुरू करने का निर्णय लिया है और तदनुसार ‘प्रस्ताव हेतु निवेदन’ (आरएफपी) जारी किये है, जो इन लिंकों के अंतर्गत उपलब्ध है।
https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html and https://www.bankeauctions.com.
- उपरोक्त संपत्तियों से संबंधित दस्तावेज इन लिंकों के अंतर्गत जाकर देखे जा सकते हैं :
https://www.sebi.gov.in/notice-for-eoi-proposals.html and https://www.bankeauctions.com.
- ई-नीलामी में और लेने से संबंधित ब्यौरे आरएफपी में दिए हुए हैं। आरएफपी से संबंधित मुख्य मुख्य तारीखें इस प्रकार हैं :-
आरएफपी के प्रकाशन की तारीख 30 सितंबर, 2026
बोलियाँ इस तारीख से प्रस्तुत की 30 सितंबर, 2026 जा सकती हैं
बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 02 नवंबर, 2026 (17:00 बजे) और समय इस तारीख से ई-नीलामी शुरू होगी 20 नवंबर, 2026 (11:00 बजे)

- संबंधित शर्तें :**
- इन संपत्तियों की बिक्री ‘जहाँ है, जैसा है और जो भी है’ के आधार पर की जाएगी और यदि इन संपत्तियों को लेकर कोई दावा किया जाता है या उन पर कोई देनदारी बकाया हो और/या उन पर कोई ऋणभार (इन्क्वेंडेंस) हो, तो उसकी जिम्मेदारी खरीदार की होगी।
 - इस नोटिस में और इस निविदा संबंधी दस्तावेज के तहत जारी किए गए आरएफपी में संपत्तियों के जो ब्यौरे दिए गए हैं वे उसी प्रकार हैं जैसा विक्रेता को उपलब्ध कराया गया है और यदि किसी कारण से इन ब्यौरों में कोई भी बदलाव होता है, तो इसकी जिम्मेदारी न तो विक्रेता की होगी और और न ही एजेंसी की।
 - यदि संपत्तियों / उनसे संबंधित हक विलेख (टाइटल डीड) में कुछ भी गड़बड़ी पाई जाती है, तो उसके लिए समिति किसी भी सूरत में जिम्मेदार नहीं होगी और बोली लगाने वालों से यह निवेदन है कि वे संपत्तियों से संबंधित हक विलेख (टाइटल डीड) की अच्छी तरह से खानबीन करने के बाद ही अपनी बोलीयाँ प्रस्तुत करें।

CBC15204/11/0108/2627